

जरूरतमंदों तक पहुंच रहा स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी लाभ: श्री अमित शाह



सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 04 - अंक : 04 - जुलाई 2026



पांच सौ शहरों में जल्द पहुंचेगी भारत टैक्स

सरकार गरीबों व मध्यम वर्ग
को बना रही सशक्त

18

सहकारी संस्थाओं में गुणवत्ता, जवाबदेही और
पेशेवर प्रबंधन पर फोकस

27

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सहकार
जागरण

जुलाई 2026, अंक 04, वर्ष 04

संपादक मंडल

संपादक

राजीव शर्मा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया,
सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो

हमें ई-मेल करें:

sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक
मंडल का होगा।

निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),

एनसीयूआई

एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त
क्रांति मार्ग, सिरी
इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज
खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

MINISTRY OF COOPERATION



NCUI हाट

CEAS-LMS



भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

06

पांच सौ शहरों में जल्द पहुंचेगी
भारत टैक्सी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया है। इस मंत्र को मोबिलिटी और यातायात क्षेत्र में साकार करने की दिशा में भारत टैक्सी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह देश के टैक्सी सारथियों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का मजबूत माध्यम बन रही है।



12

जरूरतमंदों तक पहुंच रहा
स्वास्थ्य योजनाओं
का प्रभावी लाभ: श्री अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार
ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन
किया है।



भारत ने 'वन अर्थ, वन फेमिली, वन प्लूचर' का पूरी दुनिया को दिया संदेश

14

विकसित भारत की यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान

15

उपज की आनलाइन बिक्री से बिचौलिए होंगे खत्म, किसानों को मिलेगा पूरा लाभ

16

विकास के साथ विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार कटिबद्ध : श्री अमित शाह

20

भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत की उन्नति जरूरी : पीएम श्री नरेन्द्र मोदी

22

हरियाणा और राजस्थान की पानी से जुड़ी तीन दशक पुरानी समस्या का हुआ समाधान

24



29

रामगढ़ की सहकारी समिति
ने कायम की मिसाल



सहकार से समृद्धि को साकार कर रही भारत टैक्सी

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में भारत टैक्सी की पहल अब देशव्यापी विस्तार की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसी वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में इसके औपचारिक शुभारंभ के समय ही इसे वर्ष 2027 तक देशव्यापी बनाने का उद्घोष कर दिया था। दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसका विस्तार हो रहा है और हाल ही में गुजरात के 14 शहरों में भी भारत टैक्सी पहुंच चुकी है। यह सहकारी योजना कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैलाने के लक्ष्य के साथ ही शीघ्र ही इसे देश के 500 शहरों तक पहुंचाने की दिशा में पहल तेज हो गई है। यह कोऑपरेटिव मूल्यों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भारत का सबसे सुलभ, यूजर-केंद्रित और भविष्य का एक भरोसेमंद मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बन रहा है।

सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी को देश का सबसे भरोसेमंद मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने और सारथियों को सम्मान के साथ काम करने का परिवेश प्रदान करने के साथ ही यहां राइडर्स को पारदर्शी और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल रहा है। इस सहकारी पहल को निष्पक्ष और समावेशी विकास के साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' की भावना से प्रेरित एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां मोबिलिटी हो, और उसका मालिकाना हक उन लोगों के पास हो जो इसे चलाते हैं। 'सारथी ही मालिक' के मूल मंत्र के साथ भारत टैक्सी में निजी कंपनियों की मुनाफा अर्जित करने की लालसा के विपरीत यहां ड्राइवर यानी सारथी को मालिकाना हक दिया गया है और राइडर से पारदर्शी किराया ही लिया जाता है। यहां 500 रुपये के न्यूनतम निवेश पर सारथी को मालिकाना हक मिल रहा है। 'सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड' के जरिए जीरो कमीशन, तुरंत पेमेंट और पूरा मालिकाना हक सुनिश्चित करना एक ऐसी पहल है, जिससे सारथी समुदाय को मजबूती मिल रही है और उनमें एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ है।

भारत टैक्सी की यह विकास यात्रा यात्रियों व सारथियों के लिए सकारात्मक बदलाव की एक ऐसी लहर पैदा कर रही है, जहां ड्राइवरों के बेहतर जीवन के साथ समुदायिक विकास सुनिश्चित हो रहा है। यहां सारथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'बाइक दीदी' जैसी पहलें चलाई जा रही हैं, जिनके तहत अब तक हजारों महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं। भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म व विश्व का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जहां सात लाख से अधिक ड्राइवर और 37 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि अब तक सीधे ड्राइवरों में वितरित की जा चुकी है।

आशा ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि सहकारिता की यह पहल देश के मोबिलिटी सेक्टर में स्वस्थ परंपराओं के विकास और सारथियों के हितों के संरक्षण का एक ऐसा आदर्श कायम करेगी, जो वैश्विक पटल पर एक मिसाल होगा।

जय सहकार



हमारे किसान भाई-बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधारस्तंभ हैं। उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। खेती सहित अन्य जरूरतों के लिए कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के बहुत काम आ रहा है। उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 'बीज से बाजार तक' की हमारी पहल भी बहुत कारगर साबित हो रही है।



श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



मोदी सरकार का 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' मॉडल नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण का नया अध्याय लिख रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और 12 करोड़ से अधिक शौचालयों तक, महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुद्रा योजना से 70 प्रतिशत महिलाओं को बिना गारंटी लोन देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। 'लखपति दीदी', 'करोड़पति दीदी' और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया है।



श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



किसान और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) देश की आधारभूत संरचना हैं। कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 18-20 प्रतिशत योगदान है। बदलते समय में कृषि के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान सहकारिता, नवाचार और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से करना होगा।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री



पिछले पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति और अभूतपूर्व विस्तार किया है। कृषि ऋण तक सीमित रहने वाली सहकारिता आज डेयरी, मत्स्य पालन, शुगर, परिवहन और अनेक नए क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऑनलाइन सीएससी सेवाओं से लेकर पेट्रोल पंप, उचित मूल्य की दुकानों और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी सुविधाओं तक, 'सहकार से समृद्धि' का संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है।

श्री मुरलीधर मोहोले
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में सुशासन और जनकल्याण की नीतियों ने महिलाओं के डिजिटल एवं आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति प्रदान की है। यह परिवर्तनकारी यात्रा दशाती है कि जब नारी शक्ति को अवसर, तकनीक और विश्वास मिलता है, तो वह न केवल अपने सपनों को साकार करती है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की सशक्त आधारशिला भी बनती है। इन वर्षों में 3.6 करोड़ से अधिक महिलाओं को डिजिटल साक्षरता से जोड़ा गया, 48 फीसदी स्टार्टअप्स में कम-से-कम एक महिला निदेशक की भागीदारी जुड़ी, तीन करोड़ से अधिक महिला नेतृत्व वाले, एसएसएमई रोजगार सृजन में योगदान दे रहे हैं।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

मन की बात के 135वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संस्कृत विश्वविद्यालय में होगी डेटा साइंस व एआई की पढ़ाई

सहकार जागरण टीम

हा

ल ही में देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हर देशवासी को गर्व

से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौ-सेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये जहाज पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसी प्रकार देश में ही निर्मित सी-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। ऐसे 40 विमान और भारत में बनाए जा रहे हैं। डीआरडीओं ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर लंबी दूरी की मिसाइल का भी सफल प्रक्षेपण किया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और समुद्र से लेकर आकाश तक भारत अधिक सुरक्षित व आत्मनिर्भर बन रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में कही।

अपने नए अवतार के रूप में सीने में हजारों साल का इतिहास समेटे नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बदलते समय और नई तकनीक के साथ अपनी जड़ों से जुड़ने की कला यह विश्वविद्यालय सिखाता है। तकनीक, अनुसंधान और रोज हो रहे नए-नए एआई नवाचार के युग में नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवंत किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है। ये वादग्रस्तवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ



▶▶ भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संकल्प हो रहा मजबूत

▶▶ भारत में ही पूर्ण रूप से बनाए जा रहे सैन्य हवाई जहाज, पोत और मिसाइलें

की प्रक्रिया से मिलती है। प्राचीन परंपरा को वर्तमान युग से जोड़ने का विश्वविद्यालय का प्रयास बहुत सराहनीय है।

अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई तकनीक के लिए किए जा रहे प्रयासों को उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा साइंस में बी.टेक कोर्स शुरू करने जा रहा है। ये आधुनिक तकनीक को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी।

भारतीय संस्कृति के दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने और यहां के गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया-भर के लोगों

के जानने और अपनाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या लगभग 100 या इससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है।

वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है, 'ब्रह्मकमल डोमिनिकाना'। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम शामिल हैं। ■



पांच सौ शहरों में जल्द पहुंचेगी भारत टैक्सी

सहकार जागरण टीम

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया है। इस मंत्र को मोबिलिटी और यातायात क्षेत्र में साकार करने की दिशा में भारत टैक्सी एक महत्वपूर्ण पहल

है। यह देश के टैक्सी सारथियों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का मजबूत माध्यम बन रही है। कुछ महीने पहले ही राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ भारत टैक्सी का कारवां अब गुजरात में पहुंच गया है। राज्य के ज्यादातर प्रमुख शहरों में भारत टैक्सी का संचालन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर से गुजरात के लिए इसकी आधिकारिक लांचिंग की और इसे जल्दी ही देशव्यापी बनाने का संकल्प व्यक्त किया। भारत टैक्सी का उपयोग अब तक 37 लाख लोगों ने शुरू कर दिया है। जबकि भारत टैक्सी के

- ▶▶ 14 शहरों में पहुंची भारत टैक्सी सेवा, सारथियों के जीवन में ला रही बदलाव, सात लाख 'सारथी' इससे जुड़े
- ▶▶ अहमदाबाद, सूरत, राजकोट सहित गुजरात के सभी बड़े शहरों में टू-व्हीलर, ऑटो और फोर-व्हीलर तीनों श्रेणियों में सेवा शुरू
- ▶▶ सेवा के संकल्प, सहकारिता की शक्ति और सारथियों के विश्वास के साथ आगे बढ़ती रहेगी भारत टैक्सी



सरकार समर्थित भारत टैक्सी एक वैकल्पिक और अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के रूप में उभर रही है। यह सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म उस पूंजीवादी सोच के खिलाफ सरकार समर्थित एक पहल है जहां ओला-उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवरों के शोषण के मॉडल को नकार कर सभी सारथियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए की गई है। यह टैक्सी सेवा ड्राइवरों को भागीदार के रूप में जोड़ती है और उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए पारदर्शिता, बेहतर कमाई और सम्मानजनक काम का अवसर देती है। इस सहकारी मॉडल से यात्रियों को भी अनावश्यक टैरिफ और किराए की मनमानी बढ़ोतरी से निजात मिला है। आने वाले दिनों में इस टैक्सी सेवा अभियान का विस्तार देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों तक विस्तार होगा।

कारवां में सात लाख से अधिक सारथी यानी ड्राइवर जुड़ चुके हैं।

गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में श्री शाह ने कहा कि देश के विकास के साथ टैक्सी और यातायात सेवाओं की आवश्यकता घर-घर तक पहुंची है। अब टैक्सी की अवधारणा चार पहिया वाहन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोपहिया, ऑटो और अन्य शहरी परिवहन सेवाएं भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं। गुजरात में 'भारत टैक्सी' की यह शुरुआत देश के मोबिलिटी क्षेत्र की व्यापक जरूरतों को सहकारिता के माध्यम से नई दिशा प्रदान करेगी। भारत टैक्सी का उद्देश्य टैक्सी, ऑटो और दोपहिया मोबिलिटी सेवाओं से जुड़े

सारथियों को मालिकाना हिस्सेदारी, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि से जोड़ते हुए नागरिकों को विश्वसनीय और सेवा-भाव आधारित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है।

टैक्सी ड्राइवरों यानी सारथियों का आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की सफलता सेवा-भाव, सहकारी भावना और सारथियों की भागीदारी से तय होगी। सारथियों ने भारत टैक्सी से जुड़कर अपनी समृद्धि, सम्मान और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। चालकों को सम्मान के साथ मालिक बनाने वाली 'भारत टैक्सी' सेवा उन्हें अधिक मुनाफा तो दे ही रही है, साथ ही इससे यात्रियों को भी सुगम व सुरक्षित टैक्सी की सेवा मिल रही है।

- ▶▶ सारथियों की अपनी कोऑपरेटिव है 'भारत टैक्सी', ऋण में सहायता, बीमा की सुरक्षा और बिजनेस एक्सपेंशन मॉडल को भी पोषित करेगी
- ▶▶ 'भारत टैक्सी' के सारथी केवल ड्राइवर नहीं बल्कि शेयर होल्डर भी, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी मिल रही



अब तक 37 लाख से अधिक लोग भारत टैक्सी से जुड़े

भारत टैक्सी के देशभर में हो रहे विस्तार पर प्रकाश डालते हुए श्री शाह ने कहा कि अब तक सात लाख से अधिक सारथी इससे जुड़ चुके हैं, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक सारथी गुजरात से ही हैं। वहीं, पूरे भारत में अब तक लगभग 37 लाख से अधिक ग्राहकों ने भारत टैक्सी की सेवाओं का लाभ उठाया है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और जनविश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। देश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक इसके विस्तार की योजना है जिस पर कार्य चल रहा है। फिलहाल 14 शहरों में भारत टैक्सी की टू-व्हीलर, ऑटो और फोर-व्हीलर सेवाएं शुरू हो गई हैं। जुलाई महीने में ही देश के सात प्रमुख स्थानों- नागपुर, पुणे, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता सहित देश के अनेक शहरों में भारत टैक्सी की सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जबकि आगामी दो वर्षों में देश के 500 से अधिक शहरों और कस्बों तक इस टैक्सी सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा।

भारत टैक्सी अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी और आने वाले वर्षों में दोपहिया, ऑटो और चारपहिया की तीनों श्रेणियों में भारत टैक्सी का मॉडल सभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा। भारत टैक्सी सारथियों को सम्मान व सुरक्षा देगी। उनकी समृद्धि का रास्ता भी यहीं से प्रशस्त होगा। यह सहकारी संस्था सारथियों की कमाई की रक्षा करने के साथ-साथ उन्हें भविष्य में ऋण, बीमा और अपने व्यवसाय के विस्तार में भी सहयोग करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात के सारथी भारत टैक्सी से जुड़कर सहकारिता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में यह सहकारी संस्था भविष्य में नई ऊंचाइयां छुएगी और निश्चित रूप से बहुत सफल होगी। सहकारिता के इस विशाल सहकारी परिवार से देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और अब गुजरात के सारथी भी इस गौरवशाली सहकारी परिवार का अभिन्न अंग बन रहे हैं।



- ▶▶ कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक सारथियों के कल्याण का एक सशक्त मॉडल बनेगी भारत टैक्सी
- ▶▶ कमीशन का कोई प्रावधान नहीं और न ही व्यस्त समय में भी किसी तरह से किराए में कोई बढ़ोतरी
- ▶▶ बिना किसी सरकारी हिस्सेदारी के पूरी तरह से सहभागी सहकारी समितियों द्वारा वित्त पोषित है भारत टैक्सी सेवा
- ▶▶ दुनिया की पहली ऐसी सहकारी टैक्सी सेवा है, जिसकी मालिकाना हक सीधे इसके चालकों के पास सुरक्षित, मुनाफे का सीधा वितरण ड्राइवरों के बीच
- ▶▶ भारत टैक्सी संचालन की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सारथियों द्वारा चुने प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे और चालकों के हितों की रक्षा करेंगे
- ▶▶ सारथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित सहायता प्रणाली जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को भी प्राथमिकता
- ▶▶ यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और किफायती सेवाएं प्रदान करना और सारथियों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना ही भारत टैक्सी का मुख्य उद्देश्य
- ▶▶ तेजी से बढ़ते 'राइड-हेलिंग' बाजार में पहले से स्थापित निजी कंपनियों से सहकारिता की शक्ति से प्रतिस्पर्धा कर आगे बढ़ रही भारत टैक्सी

सहकारी संस्था के सम्मानित भागीदार और 'मालिक' हैं सारथी

टैक्सी से जुड़ी अन्य कंपनियां वाहन चलाने वालों को जहां ड्राइवर मानती हैं, वहीं सहकारिता की भावना से बनी भारत टैक्सी उन्हें 'सारथी' मानती है। यह केवल शब्दों का अंतर नहीं, बल्कि पूरी सोच का अंतर है। 'सारथी' केवल सेवा प्रदाता नहीं,

बल्कि इस सहकारी संस्था के सम्मानित भागीदार और 'मालिक' हैं। भारत टैक्सी का मूल उद्देश्य सारथियों और ग्राहकों, दोनों का शोषण रोकना, सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना और मोबिलिटी क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। पिछले वर्षों में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर अनेक शिकायतें सामने आईं, जिनमें सारथियों की कमाई से अत्यधिक कमीशन के बहुत से मामले



“प्राइवेट सेक्टर की टैक्सी सेवाओं में जनता और ड्राइवर दोनों ही शोषण और समस्याओं का सामना कर रहे थे। कानून बनाने से इसका शत-प्रतिशत समाधान नहीं हो सकता था, इसलिए हमने कोऑपरेटिव मॉडल चुना, ताकि 'शोषण आधारित' व्यापार को खत्म किया जा सके। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो अमूल जैसे असाधारण परिणाम सामने आते हैं।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

रहे, तो कहीं भुगतान समय पर नहीं पहुंचा, और कहीं बिना सुनवाई के ही सारथियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। कई बार सही संस्थागत मॉडल ही स्थायी समाधान देता है और इसी सोच से देश में सहकारी मॉडल पर भारत टैक्सी की परिकल्पना की गई।

सहकारिता ने ग्रामीण लोगों को अधिकार और समृद्धि दी

भारत में सहकारिता ने कई क्षेत्रों में शोषण समाप्त कर लोगों को अधिकार और समृद्धि दी है। अमूल का उदाहरण देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि मात्र सौ रुपए के शेयर से सहकारी व्यवस्था से जुड़ने वाली ग्रामीण पशुपालक

बहनें आज सवा सौ लाख करोड़ रुपए के कारोबार वाले विश्वसनीय खाद्य ब्रांड अमूल की भागीदार हैं। अमूल ने यह सिद्ध किया है कि सहकारिता के माध्यम से बिचौलियों से मुक्त, बिना शोषण और पूरी पारदर्शिता के साथ एक विशाल आर्थिक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मॉडल ने दुग्ध क्षेत्र में शोषण को समाप्त किया और पशुपालक बहनों की मेहनत की कमाई को सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाया। भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की इस शीर्ष सहकारी संगठन से जुड़कर ग्रामीण भारत की पशुपालक बहनें आज अपने श्रम का पूरा मूल्य सम्मान के साथ प्राप्त कर रही हैं।

इसी प्रकार इफको और कृभको जैसी

सहकारी संस्थाएं देश के किसानों की उर्वरक आवश्यकता का लगभग 35 प्रतिशत पूरा करती हैं। यह भी सहकारिता की एक बड़ी सफलता की कहानी है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हमने अनेक सफल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अमूल को भी निजी डेयरियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, इफको, कृभको और एनडीडीबी को भी निजी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन सहकारिता की शक्ति, पारदर्शिता और जनविश्वास के बल पर ये संस्थाएं सफल हुईं।

परिवहन क्षेत्र में आगे बढ़ रही सहकारिता

भारत टैक्सी इसी सफल सहकारी परंपरा को परिवहन क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास है। भारत टैक्सी जैसी पहल के लिए संसाधन कहां से आएंगे, बहुत से लोगों के मन में उठ रहे ऐसे सवाल का समाधान करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस विषय पर देश की प्रमुख सहकारी संस्थाओं से संवाद किया गया और उन्हें इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ने का आह्वान किया गया। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि एनसीडीसी, इफको, कृभको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल और अमूल जैसी प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं ने मिलकर मोबिलिटी क्षेत्र में सारथियों की अपनी सहकारी संस्था खड़ी करने का निर्णय लिया, जिससे कि देश की बड़ी निजी कंपनियों के सामने एक सशक्त, पारदर्शी और सारथी-केंद्रित सहकारी विकल्प प्रस्तुत किया जा सके।

एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था है भारत टैक्सी

भारत टैक्सी आने के बाद घाटा उठाकर अनुचित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारत टैक्सी को बाजार से बाहर करने का प्रयास कर रही हैं। निजी कंपनियां किराया घटाकर और सारथियों को अस्थायी रूप से अधिक कमीशन देकर बाजार में दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका उद्देश्य केवल भारत टैक्सी की प्रगति को रोकना है। वे



सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी सेवा पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता सुधारना और ड्राइवरों के लिए बेहतर कमाई के अवसर पैदा करना है। सरल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, बेहतर संचालन और राइड की लगातार मांग सुनिश्चित करके यह पहल ड्राइवरों और यात्रियों के लिए एक स्थायी और समावेशी सिस्टम बनाने का विशिष्ट प्रयास है। यह सहकारी और तकनीक-संचालित मॉडल भारत के बदलते शहरी परिवहन तंत्र की रीढ़ बनेगी और भविष्य की मोबिलिटी की दिशा तय करेगी।



कंपनियां चाहती हैं कि भारत टैक्सी मैदान से बाहर हो जाए और वे फिर से अपनी मनमानी शुरू कर सकें। श्री शाह ने स्पष्ट कहा कि उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और भारत टैक्सी सेवा के संकल्प, सहकारिता की शक्ति और सारथियों के विश्वास के साथ आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी रणनीतियां दुनिया के कुछ देशों में चल सकती हैं, लेकिन भारत में नहीं चलेगी, क्योंकि भारत की आत्मा सहकारिता, सेवा और सबके कल्याण की भावना में बसती है। यहां केवल अपना लाभ नहीं, बल्कि सबका हित सर्वोपरि माना जाता है। श्री शाह ने कहा कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें हमारा उत्तर हमारी सहकारी भावना, निरंतरता और सेवा-निष्ठा से मिलेगा।

सहकारिता की भावना से गठित भारत टैक्सी के उद्देश्यों के प्रति देशभर के ग्राहकों का विश्वास मजबूत करते हुए श्री शाह ने कहा कि जहां-जहां भारत टैक्सी पहुंच रही है, वहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां घाटा सहकर अस्थायी रूप से किराए कम कर रही हैं, लेकिन यह स्थिति कब तक चलेगी? उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत टैक्सी न थकेगी, न पीछे

हटेगी और न ही मैदान छोड़ेगी। यह सेवा और सहकार की भावना के साथ मजबूती से डटी रहेगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी का नुकसान करना नहीं, बल्कि परिवहन क्षेत्र में एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और स्थायी व्यवस्था खड़ी करना है।

भारत टैक्सी को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी

वर्षों से अलग-अलग कंपनियों के साथ काम करते आए सारथियों से श्री शाह ने कहा, 'आप जानते हैं कि कई बार बिना सुनवाई के निर्णय हुए, कमाई में कटौती हुई और आपके परिश्रम का पूरा सम्मान नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत टैक्सी कभी आपका शोषण नहीं करेगी, क्योंकि यह कोई बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि आपकी अपनी सहकारी संस्था है।' उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सारथियों की है।

यदि हम केवल तत्काल लाभ को देखकर निर्णय करेंगे, तो आने वाले वर्षों में फिर उसी शोषण का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए भारत टैक्सी की स्थापना की गई है। श्री शाह ने सारथियों से कहा कि भारत टैक्सी आपकी अपनी संस्था है और यह आपके शोषण को रोकने के लिए बनी है, आपको सम्मान देने के लिए बनी है और आपको समृद्ध बनाने के लिए बनी है। आने वाले समय में यही संस्था आपको ऋण उपलब्ध कराने, बीमा सुरक्षा देने और आपके व्यवसाय के विस्तार में सहयोग करने का काम भी करेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य कोई निजी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उद्देश्य अपना लाभ होता है, जबकि भारत टैक्सी का उद्देश्य अपने सारथियों का कल्याण है। ऐसे में, सारथियों को अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सुरक्षा, सम्मान और स्थिर आय को प्राथमिकता देना होगी।

मार्च तक सवा सौ शहरों में पहुंच जाएगी भारत टैक्सी

दिल्ली एनसीआर के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर और द्वारका आदि 14 प्रमुख शहरों में भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है और इसे अगले एक महीने के भीतर पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सहकारी प्लेटफॉर्म निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार और ड्राइवरो व ग्राहकों के शोषण को रोकने के लिए 'सहकार से समृद्धि' के विजन के साथ स्थापित किया गया है। गुजरात हमेशा से देश में सहकारी आंदोलनों का गढ़ रहा है और यही कारण है कि इस टैक्सी सेवा को राज्य में ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। राज्य में भारत टैक्सी के औपचारिक लांच से पहले ही दिसंबर 2025 में इसके सॉफ्ट लॉन्च के दौरान ही 1.5 लाख से अधिक सारथियों और सात लाख से अधिक ग्राहकों ने इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। मार्च 2027 भारत टैक्सी सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर तक देश के 125 शहरों और 30 प्रमुख शहरी केंद्रों तक विस्तारित करने की योजना है।

जीरो-कमीशन मॉडल: बाजार में पहले से एकाधिकार स्थापित किए निजी एग्रीगेटर कंपनियों के विपरीत सहकारिता की मूल भावना के साथ भारत टैक्सी को पूरी तरह से जीरो-कमीशन मॉडल पर स्थापित किया गया है। इसका आशय यह है कि ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा गया है, वे अपनी कमाई का पूरा हिस्सा खुद रखेंगे।

सर्ज-प्राइसिंग से मुक्ति: भारत टैक्सी सेवा में यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि निजी टैक्सी कंपनियों के विपरीत व्यस्त समय या बारिश आदि की दशाओं में भी यहां किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सरचार्ज को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा: भारत टैक्सी में सारथियों को सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि 'मालिक' का दर्जा दिया गया है। इसके तहत उन्हें



स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आसान लोन और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

पुलिस के साथ सुरक्षा टाई-अप: यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस और गुजरात में भी स्थानीय पुलिस के साथ विशेष 'सेफ्टी इंटीग्रेशन' किया गया है। यात्रियों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक पहल यह है कि भारत टैक्सी सेवा के तहत बाइक, ऑटो और कैब तीनों तरह की राइड बुकिंग प्रदान की जा रही है। साथ ही, महिला यात्रियों के लिए महिला सारथी की बुकिंग की सुविधा भी मिल रही है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रबंधित है।

मजबूत को-ऑपरेटिव सपोर्ट: भारत टैक्सी नामक इस सेवा को 'सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड' ने विकसित किया है। इसे अमूल, इफको, नाबार्ड और एनसीडीसी सहित देश के आठ बड़े सहकारी संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

सभी सारथियों और ग्राहकों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि यदि हम एक दीर्घकालिक, विश्वसनीय और न्यायपूर्ण परिवहन व्यवस्था चाहते हैं, तो भारत टैक्सी को सफल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्राहकों से अपील किया कि भारत टैक्सी के साथ बने रहिए, भारत टैक्सी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी।

भारत टैक्सी को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन

भारत टैक्सी के विस्तार और सुचारु संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ

समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजकोट; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सूरत; गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन; अहमदाबाद नगर निगम व बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम; गुजरात राज्य सहकारी बैंक; अदानी एयरपोर्ट; गुजरात ट्रैफिक पुलिस; पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल और वडोदरा एयरपोर्ट शामिल हैं। भारत टैक्सी की सेवा पहुंच को इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से हवाई अड्डों, रेलवे, मेट्रो, शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में और मजबूती मिलेगी।

सर्वश्रेष्ठ सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र भी इस समारोह में वितरित किए गये। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संधवी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, गुजरात के सहकारिता राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, गुजरात के मुख्य सचिव श्री मनोज दास और भारत टैक्सी के अध्यक्ष डॉ. जयेन मेहता सहित सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में सारथियों ने आयोजन में भागीदारी की। ■



गांधीनगर में 'पीएम फैमिली केयर ट्रेकर' के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ

जरूरतमंदों तक पहुंच रहा स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी लाभ: श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। देश की जरूरत के अनुसार मेडिकल शिक्षा की सीटें बढ़ाने से लेकर करोड़ों नागरिकों के लिए पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री करने, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, आयुष के माध्यम से हमारी परंपरागत आरोग्य पद्धतियों को पुनर्जीवित करने जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन सभी पहल की मॉनिटरिंग के लिए 'पीएम फैमिली केयर ट्रेकर' की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 'पीएम फैमिली केयर ट्रेकर' (एफसीटी)



- ▶▶ 'पीएम फैमिली केयर ट्रेकर' जन्म-मृत्यु डेटा से जुड़कर हर बच्चे को यूनिक आईडी देगा, जिससे योजनाओं का लाभ स्वतः और समय पर पहुंचेगा
- ▶▶ यह लाभार्थी की पहचान, सरकारी पहुंच और योजनाओं की डिलीवरी की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगा



पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह डैशबोर्ड विभिन्न प्रकार के डेटा को जोड़कर केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद परिवारों के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इससे एक एकीकृत निगरानी प्रणाली का निर्माण होगा, जिससे जरूरतमंदों को पहचानकर उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आधारित सुशासन के इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने कहा कि इसके जरिए एक प्रकार से सभी लाभार्थियों के लिए शासन को ट्रैक करने का कार्य होगा। इसमें पूरे डेटाबेस को समाहित करके उसे जन्म-मृत्यु के डेटा के साथ जोड़ दिया जाएगा और सभी बच्चों को निश्चित पहचान संख्या दी जाएगी। यह कार्य पीएम 'फेमिली केयर ट्रैकर' से ही होगा और इसी के माध्यम से सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने डीबीटी की शुरुआत कर गरीब कल्याण के नए युग का आरंभ किया। देश के करोड़ों लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही समस्याएं श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सिर्फ 12 वर्षों में सुलझा दी। इन वर्षों में सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस सिलिंडर, पांच किलो मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया एवं 90 प्रतिशत सस्ती दवाओं की व्यवस्था की है। आजादी के बाद से पहली बार देश के करोड़ों लोगों को हमारी सरकार ने उनका हिस्सा देने का कार्य किया है।

पिलाई, उन्हें पोषण किट का वितरण किया और पीएम ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाई।

वर्ष 2014 से देश में हो रहा सर्वांगीण और सर्वस्पर्शीय विकास

श्री शाह ने कहा वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने देश के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शीय विकास की एक नई दिशाधारा तय की है। मोदी सरकार ने न सिर्फ हर क्षेत्र में दीर्घकालीन नीतियां बनाई, बल्कि

उनकी मॉनिटरिंग की और उन्हें समयबद्धता के साथ जमीन पर उतारा है। देश की सुरक्षा, संस्कृति, शिक्षा नीति, अर्थतंत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और हर क्षेत्र में नीति निर्माण एवं उनमें समयानुसार सुधार का कार्य भी हुआ है। श्री मोदी नेतृत्व में भारत के करोड़ों गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए समग्रता से प्रयास हो रहा है। सरकार आज देश के गरीब के लिए जितने भी पैसे भेजती है, वह पूरी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे गरीबों तक पहुंचती है। ■

फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

भारत ने 'वन अर्थ, वन फेमिली, वन फ्यूचर' का पूरी दुनिया को दिया संदेश

सहकार जागरण टीम

व

र्तमान में मानवता की प्रगति व समृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां जरूरी

हैं। व्यापार व तकनीक का इस्तेमाल सभी के हित में किया जाना चाहिए। भारत ने हमेशा 'मानवता सबसे पहले' के सिद्धांत का पालन किया है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के नजरिए को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सोच भारत की सभी कोशिशों के केंद्र में रही है, चाहे वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ या 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत काम करना हो। इसी समावेशी नजरिए की वजह से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है।

भारत की समावेशी और टिकाऊ विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय' के मंत्र ने वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, तकनीक के जरिए लोगों का सशक्तीकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को 'दाता-प्राप्तकर्ता' (डोनर-रिसीपेंट) वाली सोच से निकलने और समान हिस्सेदारी की ओर बढ़ने की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान न करना अंतरराष्ट्रीय एकजुटता बनाने में सबसे बड़ी बाधा है और



► **शांति और स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए**

इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने की जरूरत है। शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत के बढ़ने के साथ दुनिया की 16 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती है आगे

जी7 के मंच से निकलने वाले संदेश को पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वृद्धि का प्रश्न केवल जीडीपी का प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न यह है कि वृद्धि किसके लिए है, किसके साथ है, और किस दिशा में है। भारत का अनुभव दिखाता है कि साझा विकास की आकांक्षा को वास्तविकता में बदला जा सकता है। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत जनसंख्या

आगे बढ़ती है। इसलिए भारत की वृद्धि की कहानी पूरी मानवता के लिए समावेशी, मात्रा और लोकोतांत्रिक सशक्तीकरण की कहानी है। पिछले 12 वर्षों में भारत 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मूलमंत्र पर आगे बढ़ा है। यही हमारी वैश्विक भागीदारी का भी सिद्धांत है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वन अर्थ, वन फेमिली, वन फ्यूचर का संदेश पूरे विश्व को दिया। यह केवल एक नारा नहीं, हमारी सभ्यता की उस भावना का विस्तार था, जो विश्व को एक परिवार मानती है। इसी भावना से हमने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानि आई-मेक जैसी ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। यह कॉरिडोर व्यापार को गति देगा, सप्ताई चैन को मजबूत बनाएगा और इसके सदस्य देशों में निवेश, रोजगार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा।■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

विकसित भारत की यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान

सहकार जागरण टीम

भा

रत की प्रतिभा, कौशल
और नवाचार
डिजिटल युग की
चुनौतियों का समाधान

खोजने में दुनिया की मदद कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को भारत की प्रगति में योगदान देने और 'विकसित भारत' की यात्रा में भागीदार बनने के लिए आगे आना चाहिए। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कही। भारतीय नवाचार और विचारों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच लोगों के आपसी संबंध बढ़े हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, प्रोफेशनल और पर्यटक फ्रांस को अपना गंतव्य बना रहे हैं। दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस में यूपीआई का प्रभाव बढ़ा है। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन के प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों समावेशी विकास और महिला-नेतृत्व वाले विकास से लेकर मानव-केंद्रित एआई और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले जाने को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यूके और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते भारतीय श्रमिकों, किसानों, इनोवेटर्स और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलेंगे। नीस में 'भारत इनोवेटर्स 2026' और पेरिस में 'विवटेक 2026' में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक समुदाय के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र



- ▶▶ भारतीय नवाचार व विचारों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में प्रवासी भारतीयों की है महत्वपूर्ण भूमिका
- ▶▶ यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते से भारतीय श्रमिकों, किसानों, इनोवेटर्स के लिए खुलेंगे नए अवसर

में पसंदीदा भागीदार बनता जा रहा है। भारत विश्वास आधारित अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए दृढ़ता से खड़ा है और इस साझेदारी में 'ग्लोबल साउथ' को एक समान भागीदार के रूप में माना जाना चाहिए।

पिछले 12 वर्ष में 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य और उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत का जीडीपी दोगुना हो गया। हवाई उड़ों और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई। राजमार्ग निर्माण की गति तीन गुना बढ़ गई। मेट्रो नेटवर्क चार गुना बढ़ गया। भारत का रक्षा निर्यात 35 गुना अधिक हो गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात है। इसी गति व

प्रगति के कारण अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात देश है। आज का भारत और यहां के युवा बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। ये भारत की आकांक्षाओं को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। भारत के गांवों में भी विकास का सूरज चमकने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज दूर-दराज के गांवों में भी बिजली है, इंटरनेट है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर हर जगह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे किसान, मछुआरे, डेयरी किसान, महिलाएं, विद्यार्थी आदि तकनीक के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। ■

नेफेड के ई-ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ कर बोले श्री अमित शाह उपज की ऑनलाइन बिक्री से बिचौलिए होंगे खत्म, किसानों को मिलेगा पूरा लाभ



सहकार जागरण टीम

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए

निरंतर प्रयत्नशील है। पिछले वर्षों में दलहन, मक्का तथा अन्य उत्पादों की सीधी खरीद के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। अब इसका लाभ ग्रामीण किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को पूरी दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, तभी इससे किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा और दलहन की खेती का रकबा अपने आप बढ़ेगा, जिससे हमारा देश दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ

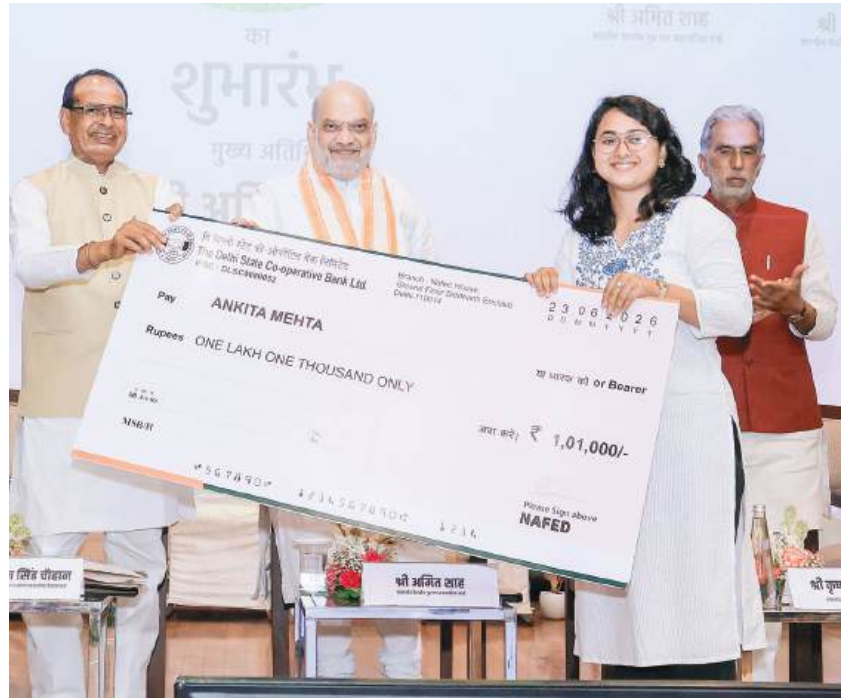
- ▶▶ अगले दो वर्षों में दलहन का एक-एक दाना सीधे किसानों से खरीदेगा एनसीसीएफ और नेफेड
- ▶▶ कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा NAFEX.in
- ▶▶ 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ आज 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा नेफेड, 2014 में बंद होने के कगार पर खड़ा था
- ▶▶ किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए नेफेड ने शुरू की छात्रवृत्ति, मुनाफे का एक हिस्सा किसान परिवारों को दी जाएगी
- ▶▶ नेफेड अब केवल कृषि उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं, जैविक खेती, बीज उत्पादन, खुदरा कारोबार, जैव उर्वरक निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी बेहतरीन प्रदर्शन

(नेफेड) के डिजिटल प्लेटफॉर्म NAFEX.in के शुभारंभ के मौके पर व्यक्त किया। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों और सहकारी संस्थाओं को देशभर के खरीदारों से सीधे जोड़ना तथा कृषि उपज की बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान और सहकारी समितियां अपनी उपज की ऑनलाइन नीलामी कर सकेंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। यह पोर्टल नीलामी से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थाओं तथा हितधारकों के हित में नेफेड की समग्र कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।

किसानों को सहयोग देने, कृषि विपणन, खरीद और सहकारिता आधारित कृषि व्यापार में नेफेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने जिन चार प्रमुख पहलों की शुरुआत की है, उसमें NAFEX.in, दृष्टि, ईआरपी और नेफेड कल्याण शामिल हैं। इन डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने और सहकारी संस्थाओं को तकनीक, पारदर्शिता तथा किसान-केंद्रित सुधारों के माध्यम से सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा भारत

श्री शाह ने कहा कि खेत से लेकर किसान के खाते तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर किसानों को उनकी उपज का पूरा मुनाफा दिलाने और दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में ये पहल काफी महत्वपूर्ण हैं। नेफेड आज उत्पादन और खरीद दोनों में काफी बढ़ोत्तरी कर चुका है। यह अब केवल कृषि उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले तीन वर्षों में जैविक खेती, बीज उत्पादन, खुदरा कारोबार, जैव उर्वरक निर्माण, खाद्य सुरक्षा



किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगा नेफेड

श्री शाह ने नेफेड की 'कल्याण' योजना के तहत किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और किसान परिवारों के होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित कर इस योजना का श्रीगणेश किया। नेफेड ने अपने मुनाफे का एक प्रतिशत किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर बनाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहयोग करेगी। यह पहल किसान कल्याण और किसानों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने की दिशा में नेफेड की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इससे नेफेड की प्रासंगिकता बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है। यह एक मजबूत, आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संगठन के रूप में उभरा है।

वर्ष 2014 में जब नेफेड गहरे आर्थिक संकट में था और बंद होने की कगार पर था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इसे पूरी पारदर्शिता के साथ चलाने का निर्णय लिया और आर्थिक सहायता प्रदान कर नेफेड को एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर दिया। श्री शाह ने कहा

कि जब सहकारिता मंत्रालय बना था, तब नेफेड का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए है और अगले दो वर्षों में यह टर्नओवर बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज 500 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ नेफेड देश के 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है। इसका शुद्ध मुनाफा 139 करोड़ रुपए से बढ़कर 405 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी कुल संपत्ति 358 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,050 करोड़ रुपए हो गई है। ■

रिपब्लिक समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

सरकार गरीबों व मध्यम वर्ग को बना रही सशक्त

सहकार जागरण टीम

दे

श निराशा के दौर से निकलकर आत्मविश्वास और अवसरों के दौर में

आ गया है। आकांक्षी जिले (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) और आकांक्षी विकासखंड (एस्पिरेशनल ब्लॉक्स) कार्यक्रम ने देश के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों को विकास का इंजन बना दिया है। इन कोशिशों ने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके लिए अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार गरीब व मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में रिपब्लिक समिट को संबोधित करते हुए कही। हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और एक बड़े नए मध्यम वर्ग के उभरने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गरीबी दूर करना सिर्फ कल्याण का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह विकास, आकांक्षाओं और सामाजिक तरक्की को बढ़ावा देने वाला एक जरिया भी है।

पिछले दशक में सरकार का ध्यान मध्यम वर्ग पर होने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन को आसान बनाना एक मुख्य प्राथमिकता रही है। रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अटकी हुई रिहायशी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप देश भर में घर खरीदने वालों को हजारों घर सौंपे गए। किराया आधारित आवास वित्त (हाउसिंग फाइनेंस), डिजिटल सेवाओं और बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को काफी बेहतर बनाया है। किराया आधारित और मध्यम आय वर्ग आवास



▶▶ हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया बाहर

▶▶ 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का सपना होगा साकार

(एसडब्ल्यूएमआईएच) कोष जैसे उपायों ने अटकी हुई हजारों आवासीय इकाइयों को पूरा करने और घर खरीदने वालों तक पहुंचाने में मदद की है।

मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने के मकसद से किए गए आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कर में राहत के उपायों से कर-मुक्त आय की सीमा काफी बढ़ गई है, इससे लोगों की खर्च करने लायक आय (डिस्पोजेबल इनकम) में बढ़ोतरी हुई है। तकनीक पर आधारित ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था और फेसलेस असेसमेंट मैकेनिज्म जैसे सुधारों के जरिए कर व्यवस्था को आसान बनाया गया है। इनसे नियमों का पालन करने का बोझ कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है।

तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में नए मौकों का फायदा उठाने में भारत के युवाओं, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप के सबसे आगे होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 'राष्ट्र

प्रथम' के सिद्धांत पर चलते हुए सुधार, नवाचार और नागरिकों पर केंद्रित शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ऐसे अभूतपूर्व बदलाव देख रही है जो पारंपरिक तौर-तरीकों को चुनौती देते हैं और साथ ही विकास और नवाचार के नए अवसर भी पैदा करते हैं।

श्री मोदी ने दोहराया, सरकार इस बदलाव के सफर में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यह गति और तेज होती जाएगी। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों और आकांक्षाओं से 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा। आज लिए जा रहे फैसले और उठाए जा रहे कदम आने वाली सदियों के लिए देश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। देश न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, बल्कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर भी सामने आया है। ■

प्रगति की 52वीं बैठक में 30 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा लंबित मुद्दों का मिशन मोड में हो समाधान : पीएम श्री नरेन्द्र मोदी

- ▶ ठोस योजना व उनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के प्रभावी उपयोग पर जोर
- ▶ साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, समन्वित प्रतिक्रिया और ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था पर बल



सहकार जागरण टीम



नियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ाती है, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करना चाहिए तथा उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक में चार राज्यों में फैली 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरीडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कही। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर की नवीनतम स्थिति दिखाई देनी चाहिए ताकि रूकावटों के बारे में पहले से पता चल सके और विभिन्न एजेंसियों के

बीच तालमेल बेहतर हो तथा विश्वसनीय एवं वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जा सकें। परियोजनाओं के विवरण, उपयोगिताओं, अवसंरचना परतों, स्वीकृतियों और अन्य क्षेत्रीय सूचनाओं को पोर्टल पर नियमित एवं समय पर अपडेट करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर बल

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने जागरूकता, रोगियों के फॉलो-अप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और 'माय भारत' स्वयंसेवकों की एक टीम गठित करने का सुझाव दिया।

साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों

का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक विभाग या एजेंसी से दूसरी एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट जवाबदेही, त्वरित प्रतिक्रिया, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल मंचों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन-जागरूकता अभियानों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से रोकथाम, रिपोर्टिंग, जांच और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। ■

विकास के साथ विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार कटिबद्ध : श्री अमित शाह



सहकार जागरण टीम

दे

शहर में 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र के तहत भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। महाराष्ट्र में सभी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ मंदिर पुनर्निर्मित हो रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सार्वजनिक समारोह में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि कोल्हापुर में पवित्र करवीर क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों पहले स्थापित माता अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया है। इससे महाराष्ट्र में एक

- ▶ विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सुरक्षित भारत और वैश्विक सम्मान की सिद्धियों के रूप में इतिहास में दर्ज होगा प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह सेवाकाल
- ▶ 1500 करोड़ की लागत से अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत महाराष्ट्र में एक बार फिर धर्म और संस्कृति के शासन का आरंभ है
- ▶ ग्रामीण-सहकारी विकास से लेकर सेमीकंडक्टर, क्वांटम और न्यू-एज टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में भारत को दिलाई नई पहचान

बार फिर धर्म के शासन और सांस्कृतिक जागरूकता को नई ऊंचाई मिली है। इस परियोजना के अन्तर्गत 28,000

वर्ग मीटर से अधिक भूक्षेत्र पर 1500 करोड़ रुपये की लागत से कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के

पूरा होने पर कोल्हापुर का यह पावन तीर्थ स्थल छह माह के भीतर एक पूर्ण विकसित यात्रा धाम बन जाएगा। इससे न केवल अंबाबाई माता के लाखों भक्तों में भक्ति का पुनर्जागरण होगा, बल्कि कोल्हापुर और महाराष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और प्रचारित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करेगा।

सातवीं शताब्दी में स्थापित इस प्राचीन मंदिर के पुनर्विकास के दौरान पुरातत्व विभाग के परामर्श से आसपास के लगभग 41 छोटे-बड़े मंदिरों के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए एआई आधारित सुरक्षा कैमरों, एलईडी प्रकाश सज्जा, आउटडोर गैलरी, हेरिटेज वॉकवे, लाइट एवं साउंड शो, मल्टीपर्पस हॉल, अन्नछत्र, पुलिस चौकी तथा हेरिटेज कोर्टयार्ड सहित पूर्ण यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास, आस्था और संस्कृति के अमूल्य धरोहर रूपी इन पावन स्थानों का विकास और महिमा-मंडन सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है।

असंभव माने जाने वाले अनेक कार्य पिछले 12 वर्षों में पूरे हुए

श्री शाह ने कहा कि जब वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अबतक उन्होंने देश में असंभव माने जाने वाले अनेक कार्य पूरे किए हैं। जब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो श्री मोदी के सावाकाल के इन वर्षों को भारत के विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सुरक्षित भारत की रचना और विश्व पटल पर भारत के सम्मान में वृद्धि की उपलब्धियों के साथ दर्ज किया जाएगा। श्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण-संवर्धन के साथ ही अनेक क्षेत्रों में न केवल काम शुरू किए गए, बल्कि उन्हें पूर्णता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर अपनी दिव्य भव्यता के साथ निर्मित हो



गया है। साथ ही, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण और केदारधाम व बद्रीधाम का पुनर्निर्माण हुआ है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर को फिर से सोने का बनाया जा रहा है। असम में मां कामाख्या का कॉरिडोर भी बन रहा है और अब अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर जीर्णोद्धार एवं कॉरिडोर निर्माण कार्य भी हो रहा है।

भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य

किए हैं। ग्रामीण एवं शहरी विकास के साथ ही कृषि को समृद्ध बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, नगर नियोजन के नए मानक स्थापित किए गए और पीएलआई स्कीम लाकर भारत को वैश्विक उत्पादन का हब बनाया गया। सेमीकंडक्टर, क्वांटम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर और न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने की ठोस शुरुआत की गई है। ■

ओडिशा को 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत की उन्नति जरूरी : पीएम श्री नरेन्द्र मोदी



सहकार जागरण टीम

ओ

डिशा पूर्वी भारत में विकास और समृद्धि के प्रवेश-द्वार के रूप में उभर रहा है। राज्य

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ओडिशा के प्रचुर संसाधनों को विकास और समृद्धि के अवसरों में बदल रही है। भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास अपरिहार्य है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कही।

पूर्वोदय नीति से क्षेत्र की संभावनाएं आ रही हैं सामने

केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' नीति पूर्वी राज्यों की विशाल संभावनाओं को सामने ला रही

▶▶ ओडिशा और भारत की उम्मीदें एक समान, एक मजबूत ओडिशा एक मजबूत भारत बनाने में देगा योगदान

▶▶ जनजातीय समाज के विकास के लिए जनजातीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है

है का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों रेलवे अवसंरचना, राजमार्ग, आर्थिक कॉरिडोर, पत्तन, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और आधुनिक उद्योगों में रिकॉर्ड निवेश के जरिए इन ताकतों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं। लगभग 47,000 करोड़ रुपए की परिवर्तनकारी परियोजनाएं ओडिशा के लोगों के लिए परिवहन-संपर्क, सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार लाएंगी। इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी।

उत्कर्ष ओडिशा पहल से आया 20 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव

'उत्कर्ष ओडिशा' जैसी पहलों का उल्लेख

करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत ओडिशा ने पहले ही लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं, जबकि 3.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं कार्यान्वयन-चरण में हैं। राज्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है, जबकि 'समृद्ध शहर योजना' के जरिए शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले सालों में इन पहलों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रशासन को सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर न भटकना पड़े।

इसके परिणामस्वरूप युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम नागरिकों की उम्मीदें तेजी से पूरी हो रही हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

ओडिशा सरकार की कई प्रमुख कल्याणकारी पहलों 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद, 'सुभद्रा योजना' के तहत एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक मदद, आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, माधो सिंह हाट खर्चा योजना के तहत आदिवासी छात्रों को समर्थन और श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजों को फिर से खोले जाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने पूरे क्षेत्र में चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी सराहना की और 'स्वच्छता के माध्यम से स्वागत' की पहल को अत्यंत सराहनीय बताया।

जनजातियों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

जनजातीय कल्याण की बात करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय क्षेत्रों के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद कर कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से बुनियादी सेवाओं और अवसरचना से वंचित रखा गया था, ऐसे में जनजातीय विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आवास से संबंधित विभाग जनजातीय गांवों में जीवन स्तर सुधारने के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं। पीएम जनमन मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं सीधे सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के दरवाजे तक पहुंचें। जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 750 स्कूलों को मंजूरी दी गई



है। 1.5 करोड़ से ज्यादा जनजातीय छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर सैकड़ों करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है। मयूरभंज जिले में एक और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है।

जनजातीय समुदायों में सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने इस बीमारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। चार करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं और लाखों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गये हैं। साथ ही जिल जीवन मिशन देश भर के घरों में, जिसमें जनजातीय इलाके भी शामिल हैं, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। ओडिशा और भारत की उम्मीदों को एक समान बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक मजबूत ओडिशा एक मजबूत भारत बनाने

में योगदान देगा।

इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गांव को सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा तथा हर घर में सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के उदाहरण देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि पहाड़पुर एक मॉडल सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल-इंजन सरकार राज्य के विकास की गति को तेज कर रही है और कल्याणकारी योजनाओं, निवेश, औद्योगिक विकास व रोजगार के अवसरों के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला रही है। ■

यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर पहल

हरियाणा और राजस्थान की पानी से जुड़ी तीन दशक पुरानी समस्या का हुआ समाधान

सहकार जागरण टीम

य

मुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान सरकार

और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में इस समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग तीन दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। इससे दोनों राज्यों को लाभ होगा और पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ होगी। साथ ही कृषि, उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी और भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस समझौते से राजस्थान और हरियाणा, विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के निवारण में बहुत सहायता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि जो पानी किसी काम नहीं आ रहा था, इस समझौते के बाद अब वह पानी लोगों की प्यास बुझाने और बड़े तालाबों में संचयित होकर भूजल स्तर बढ़ाने के काम आएगा।

यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और राज्यों के बीच उत्कृष्ट सामन्जस्य एवं सहकारी संघवाद के व्यावहारिक अनुपालन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि अगर राज्य सहकारी संघवाद की सोच को आगे बढ़ाएं तो तीन दशक पुरानी समस्या भी सरलता से सुलझ सकती है। श्री शाह ने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के लिए पारस्परिक लाभ की स्थिति का अच्छा उदाहरण है। इसके तहत यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 5800 लाख



► इस समझौते से राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ-साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में भी पेय जल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई

घन मीटर पानी तीन भूमिगत पाइप लाइनों के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इन तीनों पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से भी अधिक है। इनके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी। श्री शाह ने कहा कि समझौते में वित्तीय जिम्मेदारी, लागत साझीकरण, जल आवंटन और जल छोड़ने के प्रोटोकॉल और रखरखाव का विशेष ध्यान रखा गया है। वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण इस समझौते में बुनियादी ढांचे का संचालन, रखरखाव, निगरानी तंत्र, पारदर्शिता के उपायों और विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी बहुत बढ़िया तरीके से समाहित किया गया है।

हरियाणा, राजस्थान और विशेषकर केंद्रीय जल आयोग ने इस समझौते का जो प्रारूप बनाया है, वह आने वाले कई दशकों तक विवादहीन समझौते के रूप में स्थापित रहेगा। श्री शाह ने कहा कि इस समझौते के

बाद राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ-साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में भी पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी पहुंचाना है। इससे राजस्थान राज्य अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल के लिए सतही पानी के बंटवारे पर 1994 के समझौते के तहत मिले पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश वाले इलाकों में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। यह समझौता केंद्र सरकार और समझौते में शामिल राज्य सरकारों के एकजुट प्रयासों से परियोजना को समय पर लागू करने का आधार बनेगा। ■

कोलकाता में तीन युद्धपोत नौसेना में शामिल

समृद्धि की रक्षा को सुरक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अपरिहार्य : पीएम श्री मोदी



सहकार जागरण टीम

ए

क समय ऐसा था जब भारत विश्व के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक था, इससे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती थीं। वर्ष 2014 के बाद प्रमुख नीतिगत सुधारों और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पर बल देकर इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस प्रयास किए गए। सुरक्षा समृद्धि की रक्षा के लिए अपरिहार्य है, जबकि आत्मनिर्भरता भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का जलावतरण करते

▶▶ आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का जलावतरण आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण

▶▶ जिस देश की समुद्री शक्ति सुदृढ़ होती है, उसका आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होता है

हुए कहीं। 2014 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन लगभग 40 हजार करोड़ रुपए होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि अब यह बढ़कर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की दशार्ता है। पिछले 12 वर्षों में हुई प्रगति यह दशार्ता है कि जब नीतियां स्पष्ट हों, दिशा सही हो और सभी हितधारक राष्ट्रीय विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ मिलकर

काम करें, तो परिवर्तनकारी बदलाव कैसे संभव हो सकता है।

ब्लू इकोनॉमी और समुद्री विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभर रहा पश्चिम बंगाल

भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी देश की समुद्री विरासत की चर्चा होती है, पश्चिम बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। भारत के विश्व से



समुद्री संबंधों में बंगाल ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हुगली नदी के जल ने इतिहास के बदलते अध्यायों, व्यापार के विकास और विकास की नई यात्राओं को देखा है। आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, समुद्री विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और तटीय विकास का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। भारत ने हमेशा महासागरों को सहयोग और संपर्क के माध्यम के रूप में देखा है। आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इन्हीं आदर्शों का प्रतीक हैं। वे एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक जागरूक है, अपनी शक्ति को लेकर आश्वस्त है और इक्कीसवीं सदी में नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले ये जहाज आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी हैं।

विकास, सुरक्षा और समृद्धि का महासागरों से घनिष्ठ संबंध

21 जून को विश्व जलविज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इसे एक उल्लेखनीय संयोग बताया कि भारत का सबसे उन्नत जलविज्ञानीय सर्वेक्षण पोत, आईएनएस संशोधक इसी दिन सेवा में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकीय और समुद्री क्षमताओं को दर्शाती है। आधुनिक विश्व में समुद्री शक्ति के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत समुद्री क्षमताओं के बिना कोई भी राष्ट्र एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर नहीं सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। विश्व का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। विशाल वैश्विक डेटा नेटवर्क महासागरों के नीचे संचालित होते हैं। महत्वपूर्ण खनिज, गहरे समुद्र के संसाधन और ऊर्जा के भविष्य के स्रोत तेजी से समुद्री क्षेत्र से जुड़ते जाएंगे। किसी राष्ट्र का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव सीधे उसके समुद्री क्षेत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ है। भारत इस



वास्तविकता को भलीभांति समझता है और उसी के अनुरूप तैयारी कर रहा है। तीनों नौसैनिक पोतों का जलावतरण देश की बढ़ती क्षमताओं और कौशल का प्रमाण है।

भारत के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त के जलावतरण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की समुद्री यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत की और विश्व को भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का बोध कराया। आईएनएस विक्रान्त से लेकर आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक के जलावतरण तक का सफर केवल नए युद्धपोतों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। ये तीनों पोत स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और नवोन्मेषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। भारत में डिजाइन और निर्मित ये पोत भारतीय उद्योगों की प्रतिभा, भारतीय इंजीनियरों की विशेषज्ञता और भारतीय श्रमिकों की कड़ी मेहनत प्रदर्शित करते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। देश की सैन्य शक्ति का आकलन वैश्विक बाजारों पर उसकी निर्भरता से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की उसकी क्षमता से किया जाता है। भारत एक उत्पादक और विनिर्माता बनना चाहता है, क्योंकि जो देश उत्पादन करते हैं, वे

वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी निर्मित युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग हर कुछ हफ्तों में नौसेना को एक नई क्षमता प्राप्त होती है, जबकि 45 प्रमुख नौसैनिक प्लेटफार्म वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। ये आंकड़े केवल संख्याएं भर नहीं हैं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के सूचक हैं। समुद्री क्षेत्र की असीम रोजगार सृजन क्षमता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समुद्री क्षेत्र को एक पृथक उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में देखती है। एक आधुनिक जहाज के निर्माण में बड़ी मात्रा में इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और हजारों पुर्जों की आवश्यकता होती है, इससे व्यापक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवसर उत्पन्न होते हैं। तीन कमीशन किए गए जहाजों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान रहा। इससे पूरे देश में पर्याप्त रोजगार और आर्थिक कार्यकलापों का सृजन हुआ। ■

श्रीनगर में आठवां राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन

सहकारी संस्थाओं में गुणवत्ता, जवाबदेही और पेशेवर प्रबंधन पर फोकस

सहकार जागरण टीम

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के अनुरूप केंद्रीय

गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में सहकारी विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने, विकास कार्यों को तेज करने, विभिन्न सहकारी पहलों व नीतियों को लागू करने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय समीक्षात्मक आयोजनों के माध्यम से उन्हें दिशा दे रहा है। देशभर में सहकारी आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान करने के इस क्रम में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आठवें राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां देशभर के सहकारी प्रतिनिधियों ने सहकारिता के सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाने को लेकर अपने अनुभव साझा किए। इसमें सहकारी क्षेत्र में सुधारों, नई समितियों, खासकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), जिला सहकारी समितियों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन, डिजिटल परिवर्तनों और किसानों-महिलाओं व युवाओं को केंद्र में रखकर विकास कार्यों को तेज करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कार्यान्वयन को तेज करने पर जोर दिया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी सहकारी और समावेशी विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण, बेहतर संस्थागत सहयोग और अधिक मजबूत बाजार संपर्कों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

'सहकार से समृद्धि- विजन से जमीनी वास्तविकता तक' विषय पर आयोजित



- ▶▶ सहकारी क्षेत्र के भविष्य के विजन और रोडमैप पर विचार-विमर्श के दौरान सहकारी सुधारों को अमल में लाने पर जोर
- ▶▶ यूपीआई और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म अपनाने होंगे
- ▶▶ डेयरी, कम्प्रेस्ड बायोगैस और चीनी उद्योग के उप-उत्पादों सहित सहकारी क्षेत्रों में स्थिरता और सर्कुलैरिटी पहलों की आवश्यकता पर जोर
- ▶▶ राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2.0 डेटा-आधारित गवर्नेंस को मजबूत करेगा और सहकारी संस्थाओं को सीधे डेटा अपडेट और वैलिडेट करने में सक्षम बनाएगा

सम्मेलन में सहकारी क्षेत्र के भविष्य के विजन और रोडमैप पर विचार-विमर्श किया, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने श्रेष्ठ सहकारी कार्यप्रणालियों, सफल मॉडल, नवाचार और जमीनी स्तर पर सहकारी विकास की उपलब्धियों एवं आकांक्षाओं को साझा किया। सहकारिता मंत्रालय के गठन के पिछले पांच वर्षों के दौरान श्री शाह के नेतृत्व में विभिन्न बदलावकारी पहलों के जमीनी स्तर पर

क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मंत्रालय के नेतृत्व में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय महासंघों, सहकारी संस्थाओं और सहकारी व्यवस्था के प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में इस विचार-विमर्श का उद्देश्य विकासात्मक पहलों की प्रगति की समीक्षा करना, जमीनी स्तर की चुनौतियों की पहचान करना, सफल मॉडल साझा करना और



सहकारी विकास के अगले चरण के लिए अधिक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना रहा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में देश में हो रहे सहकारी विकास और विस्तार का उल्लेख करते हुए सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन सहकारी आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक क्षण रहा। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर नियामक ढांचे से आगे बढ़कर विकासोन्मुखी और डिलीवरी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है और सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण समृद्धि, समावेशी विकास और अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी वाली संस्थाओं के रूप में मजबूत किया है। मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और सहकारिता की बुनियादी इकाई के रूप में काम करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर सुधारों पर विशेष जोर दे रहा है। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण, मॉडल बायलॉज, नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के साथ ही पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण और निर्यात, जैविक उत्पाद व बीज के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया।

सहकारी संस्थाओं में गुणवत्ता व जवाबदेही पर फोकस

नीति ढांचा और संस्थागत सहकारी तंत्र तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए सहकारिता सचिव ने कहा कि अगला चरण कार्यान्वयन, मापनीय परिणामों और जमीनी स्तर पर प्रभावी डिलीवरी पर केंद्रित होगा। अब समय आ गया है कि संख्या से आगे बढ़कर सहकारी संस्थाओं में गुणवत्ता, जवाबदेही, पेशेवर प्रबंधन और जमीनी स्तर पर दिखने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सहकारी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी और डेटा-आधारित गवर्नेंस के माध्यम से मजबूत करने और यूपीआई व डिजिटल वित्तीय सेवाओं के युग में सहकारी बैंकों को प्रासंगिक एवं प्रतिस्पर्धी बने रहने के

राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं एवं संघों की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के सहकारी तंत्र को मजबूत करने में राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय किसान ऊर्ध्वकर सहकारिता (इफको), कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जैसी संस्थाओं ने सहकारिता के माध्यम से वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, बाजार समर्थन, संस्थागत विकास और क्षेत्रीय परिवर्तन में अपने योगदान एवं भविष्यलक्षी योजनाओं को साझा किया।

देश के सभी पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के जरिए सहकारी विस्तार के प्रयासों को तेज करने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से पैक्स को सशक्त, पेशेवर रूप से प्रबंधित और प्रौद्योगिकी-सक्षम जीवंत आर्थिक संस्थाओं के रूप में उभारने पर सर्वसहमति बनी। एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण पर भविष्य-केंद्रित सोच पर बल देते हुए निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों में सहकारी-नेतृत्व वाले मॉडलों को मजबूत करने एवं उत्पादकों, संस्थाओं, बाजारों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्कों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इन पहलों से सहकारी योजनाओं का कार्यान्वयन तेज होगा, जिससे क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान होगा और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिलेंगे।

लिए आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों को साझा तकनीकी समाधान, मजबूत गवर्नेंस प्रणाली और बेहतर सेवा डिलीवरी साथ ही अधिक वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग पर जोर देते हुए सहकारी संस्थाओं को कंप्यूटरीकरण से आगे बढ़कर बेहतर गवर्नेंस, सेवा डिलीवरी और योजना निर्माण के लिए पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणालियों के विकास पर जोर दिया गया।

डेयरी, कम्प्रेस्ड बायोगैस और चीनी उद्योग के उप-उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र में स्थिरता और सकुलैरिटी पहलों की विशेष रूप से आवश्यकता पर भी जोर देते हुए सहकारिता सचिव ने कहा कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अपशिष्ट को मूल्य में बदलने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाने और अपने सदस्यों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इन संस्थाओं के गठन

में तेजी लाने का आह्वान करते हुए सचिव ने कहा कि पैक्स सहकारी ढांचे की रीढ़ हैं। प्रौद्योगिकी, मॉडल बायलॉज, व्यवसाय विविधीकरण और बेहतर गवर्नेंस के माध्यम से इन्हें मजबूत करना 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2.0 सहकारी क्षेत्र में योजना निर्माण, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगा। उन्नत प्लेटफॉर्म सहकारी संस्थाओं को सीधे डेटा अपडेट और सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे नीति समर्थन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उपलब्ध जानकारी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सभी राज्यों को विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को मजबूत करने दिशा में तेजी से काम करने का आह्वान किया गया। इससे देश के सभी किसानों को जल्द ही अन्न भंडारण सुविधाएं गांवों के नजदीकी क्षेत्र में मिल सकेंगी और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को मजबूती मिलेगी। ■

रामगढ़ की सहकारी समिति ने कायम की मिसाल

सहकार जागरण टीम

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन केंद्रीय गृह व

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में साकार होता जा रहा है। इस दिशा में सहकारी समितियों की भूमिका बहुत अहम साबित हो रही है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, रामगढ़ आदर्श ग्रामीण विकास व किसान कल्याण तथा अन्य विविध सेवाओं के माध्यम से एक मिसाल बन चुकी है।

सन 1963 में गठित इस समिति के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 723 है। समिति के कार्य क्षेत्र में रामगढ़ पिपरोली, नंगाला, सरेहटा, गोहा व चोकी गांव शामिल है। शुरू में यह प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के रूप में कार्य करती थी, बाद में बहुउद्देशीय बन गई। उतार-चढ़ाव से गुजरती समिति पर एक समय दो करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। 2021 में इसका विभाजन कर एक अन्य समिति के गठन के बाद इसका कर्ज घटकर 60 लाख रुपए हो गया। इसके बाद समिति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुशल प्रबंधन, किसानों से निरंतर संपर्क और नवाचारों के जरिए समिति ने खुद को पुनर्जीवित किया। वर्तमान में समिति ने अपने सदस्यों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान किया है। समिति का खाद-बीज का कारोबार वर्ष 2022-23 के 15-16 लाख रुपए टर्नओवर के मुकाबले वर्ष 2025-26 में बढ़कर 90 लाख रुपए तक पहुंच गया।

समिति अपने सदस्य किसानों को ऋण वितरण के साथ ही सहकार सुपर मार्केट, कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, मृदा परीक्षण केंद्र, एफपीओ और श्री अन्न (मिलेट) स्टोर आदि आधुनिक सेवाओं



▶▶ खाद-बीज के साथ ही किसानों को प्रदान किया जाता है

अल्पकालीन कृषि ऋण

▶▶ किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए भी समिति ने उपलब्ध

कराया है प्लेटफॉर्म

का संचालन करती है। एफपीओ के रूप में किसानों के उत्पादों को समिति की ओर से संचालित सुपर मार्केट और श्री अन्न (मिलेट्स) स्टोर के जरिए सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। इससे किसानों को अच्छा-खासा मुनाफा हो जाता है और ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे दैनिक उपयोग समेत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कम दाम पर मिल जाती हैं। श्री अन्न के जरिए पारंपरिक पौष्टिक आहार को भी बढ़ावा मिलता है। समिति किसानों के लिए मृदा परीक्षण की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के जरिए गांव में ही किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि उनके खेत में किस चीज की कमी है। परीक्षण के आधार पर किसानों को उर्वरकों की सही मात्रा और फसलों के चयन का भी परामर्श दिया जाता है। इसके आधार पर खेती करने से किसानों के मुनाफे में वृद्धि होती है। इससे खेती की लागत में कमी आती है और

किसानों के जीवन स्तर में सुधार होता है। समिति कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए गांव में किसानों को अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। बिजली बिल, पैन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण जैसी डिजिटल सेवाएं घर बैठे प्रदान करती है। इसके लिए किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ता। इससे उनके पैसे व समय दोनों की बचत होती है। इसका इस्तेमाल वे फसल उत्पादन में करते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के जरिए किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने के साथ उन्हें जागरूक भी किया जाता है। इससे किसानों को लाभ होता है और उनका जीवन खुशहाल होता है। समिति की उपलब्धियों के लिए 20 जून 2023 को मुंबई में आयोजित नेशनल इवेंट में रामगढ़ पैक्स को राजस्थान का पहला नैफेड बाजार बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह अवॉर्ड श्री अमित शाह ने प्रदान किया। ■



डॉ. शाजी कृष्णन ती

प्रा

थमिक कृषि ऋण
समितियां (पैक्स)
ग्रामीण विकास
की रीढ़ हैं। इनके

सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार की सहकारिता मंत्रालय की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलना सुनिश्चित हो रहा है। भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत हो रहा है और देशभर में नई, मजबूत एवं तेजी से उभरती हुई पैक्स का प्रसार हो रहा है। सहकारी सुधारों और नई सहकारिता नीति के जरिए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस होकर ये पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए योगदान कर रहे हैं। पैक्स के कारोबारी दायरे के विस्तार और उनमें दो दर्जन से अधिक नई गतिविधियों के जुड़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी कम हो रही है, वहीं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सवा लाख से अधिक पैक्स से सीधे जुड़े करीब 14 करोड़ किसानों को रोजगार और आय सृजन में लाभ हो रहा है।

हमारे देश में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुप्रबंधन, संकट के समय पर्याप्त सरकारी समर्थन की कमी और आवश्यक सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इसका विकास बाधित रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर और सहकारिता क्षेत्र के पुराने जानकार गृहमंत्री श्री अमित शाह को इसकी कमान सौंपकर सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की मुहिम शुरू कर की। श्री शाह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधक कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने इन बाधाओं को दूर करते हुए बुनियादी स्तर पर



▶▶ ग्रामीण बेरोजगारी कम होने के साथ ही बढ़ रही किसानों की आय

पैक्स को मजबूत बनाने और विविधीकरण के जरिए उनकी व्यवहार्यता बढ़ा दी है। इससे सहकारिता अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है।

श्री शाह ने पैक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, वह उनके बायलाज यानी उप-नियमों में बदलाव है। पैक्स की समस्याओं से छुटकारे के लिए माडल बायलाज लाकर उन्हें बहुदेशीय बनाया गया है। इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में मदद मिली है। पैक्स अब कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे-बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन व अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आइआरसीटीसी, बस व हवाई टिकट आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक पैक्स ग्रामीण नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जल समितियों, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल व डीजल दुकानों, किसान उत्पादक संगठनों

आदि के रूप में कार्य करने में पैक्स को सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्स अब गांवों में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पैक्स की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

दशकों से कुप्रबंधन से ग्रस्त सहकारी क्षेत्र के प्रति लोगों का विश्वास जीतना सहकारिता मंत्रालय के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करीब 80 हजार पैक्स का कंप्यूटीकरण किया जा रहा है और अबतक 62,000 से अधिक पैक्स कंप्यूटीकृत हो चुके हैं। अब तक 60 हजार से अधिक पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया भी जा चुका है। पैक्स के कंप्यूटीकरण से उन्हें सीधे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से जोड़ा जा रहा है। कामन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से संचालन में एकरूपता आएगी। इससे पैक्स संचालन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में हुई इन अनूठी पहलों से यह क्षेत्र अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरे देश में संगठित रूप में काम कर रहा है, जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। सहकारिता मंत्री श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आह्वान किया है। इससे सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। ■

—अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।



'सहकार सप्ताह' के तहत अमर डेयरी, अमरेली में पौधारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह के मार्गदर्शन में अमरेली जिले की 432 सहकारी समितियों को 51 हजार पौधों का वितरण किया गया और पर्यावरण का महत्व बताते हुए उसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद नारणभाई काछडीया, अमर डेयरी के अध्यक्ष अश्विनभाई सावलिया, जिला सहकारी खरीद बिक्री संघ के अध्यक्ष जयंतीभाई पानसुरिया समेत टीम सहकार के सदस्य उपस्थित रहे।



मणिपुर में इम्फाल के सहकारी प्रबंधन संस्थान ने मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाया और सहकारी समितियों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की थीम पर एक महिला जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस आयोजन के जरिए महिलाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को परस्पर एक साथ मिलने का मौका मिला।



एनसीयूआई ने सूरत में गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के सहयोग से कोऑपरेटिव सोसायटियों के गठन पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां प्रतिभागियों ने सूरत की प्रमुख कोऑपरेटिव संस्थाओं के अध्ययन के लिए सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (सुमूल) डेयरी का दौरा कर डेयरी कोऑपरेटिव संस्था के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की।



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'एक पेड़ मां के नाम' पहल की भावना के अनुरूप गुजरात के आणंद में इरमा परिसर में देश के एकमेव सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधारोपण किया गया।



नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के साथ मिलकर सूरत में कोऑपरेटिव सोसायटियों के गठन विषय पर तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें ऑपरेटिव सोसायटियों के गठन और उनके प्रबंधन के लिए जरूरी जानकारी साझा की गई और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने में कोऑपरेटिव के महत्व पर जोर दिया गया।



वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैमनीकॉम), पुणे ने ओडिशा राज्य के सहकारी समितियों के सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (एआरसीएस) व निरीक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सहकारी प्रबंधन में क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन और क्षेत्रीय भ्रमण के जरिए सहकारी संस्थानों, जैसे डेयरी, उर्जा, कृषि-प्रोसेसिंग आदि की व्यावहारिक जानकारी साझा की गई।



पिछले 12 वर्षों में, सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया है और यह सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक, महिलाएं विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भागीदारी अवसरों के नए द्वार खोल रही है और पूरे देश में विकास परिदृश्य को बदल रही है। हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी 'सहकार से समृद्धि' को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारी का आदान प्रदान कर सके।



<https://ncuicoop.education/>

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

RNI No.: DLHI/25/A0141

Published on 05.09.2026 | Postal Registration No DL-SW-01/4214/2023-24

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ